



बिहार चुनाव परिणाम

एनडीए 200 पार ...बिहार में नीतीश सरकार

पीएम मोदी ने बिहार चुनाव को लेकर दी पहली प्रतिक्रिया

नीतीश की बंपर जीत के क्या मायने



संपादकीय बिना छात्र स्कूल

निस्संदेह, शिक्षा मंत्रालय की वह रिपोर्ट परेशान करने वाली है, जिसमें बताया गया है कि बीते शिक्षा सत्र में देश के आठ हजार सरकारी स्कूलों में किसी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया। लेकिन विडंबना यह है कि इन स्कूलों में बीस हजार शिक्षक तैनात हैं। वहीं देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सभी कक्षाएं चल रही हैं। वैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तीस विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी करके हर जगह विसंगतियां नजर आती हैं। यही वजह है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आठ हजार स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बिना दाखिले वाले स्कूलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। यह संख्या 3,812 है, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। स्थिति का दूसरा परेशान करने वाला तथ्य यह है कि इसी राज्य के बिना दाखिले वाले स्कूलों में बाकायदा करीब अठारह हजार शिक्षक तैनात हैं। कमोबेश तेलंगाना की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां 2,245 स्कूल जीरो एडमिशन वाले हैं तथा एक हजार से ज्यादा शिक्षक यहां तैनात हैं। वहीं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, जिसका स्थान इस सूची में तीसरा है, वहां 463 स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। बाकायदा 223 शिक्षक इन जीरो एडमिशन वाले स्कूलों में तैनात हैं। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इस बार के मुकाबले पांच हजार स्कूल अधिक ऐसे थे, जहां कोई विद्यार्थी दाखिल नहीं हुआ था। एक विसंगति यह भी है कि स्कूली शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन होती है, अतः केंद्र सरकार का दखल इसमें नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल तो उठता ही है। इसके बावजूद केंद्रीय शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे शून्य दाखिले की परंपरा रोकने के लिये यथासंभव प्रयास करते रहें। बहरहाल, यहां एक सवाल यह भी है कि बिना दाखिले वाले स्कूलों के शिक्षक छात्रों को स्कूल में लाने के व्यक्तिगत प्रयास क्यों नहीं करते? वैसे कुछ राज्यों के शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। जहां शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की कम संख्या को देखते हुए उनका समायोजन अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में करके संतुलन साधने का प्रयास किया है। यहां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ आदि के शिक्षा विभाग की सराहना करनी होगी, जहां एक भी स्कूल जीरो एडमिशन वाला नहीं था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के जीरो एडमिशन वाले 81 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ की। इसका मानक यह होगा कि जहां पिछले लगातार तीन शैक्षणिक वर्षों में कोई छात्र दाखिल न हुआ हो। एक परेशान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि देश के एक लाख स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा रहा है, जिसमें करीब तैंतीस लाख छात्र अध्ययनरत हैं। जाहिर है वे छात्र क्या पढ़ रहे होंगे और उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। यहां विचारणीय प्रश्न यह भी है कि छात्रों का सरकारी स्कूलों से मोहभंग क्यों हो रहा है? यह समाज विज्ञानियों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि कम फीस व पर्याप्त शिक्षक व शिक्षण व्यवस्था के बावजूद छात्र इन स्कूलों में क्यों पढ़ना नहीं चाहते? यह विडंबना ही है कि जिन संस्थानों में नौकरी सुरक्षित और सुविधाएं पर्याप्त होती हैं, वहां कर्मचारी अपना बेहतर प्रदर्शन करते नजर नहीं आते। जबकि निजी स्कूलों में कम वेतन और कम सुविधाओं के बावजूद कर्मचारी जमकर मेहनत करते हैं। वहां शिक्षकों का खूब दोहन होता है लेकिन कक्षाएं छात्र-छात्राओं से भरी होती हैं। विडंबना यह भी कि अभिभावक ज्यादा फीस देकर भी संतुष्ट नजर आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, उस दिन सरकारी स्कूलों की दशा-दिशा सुधर जाएगी। फिलहाल देश में लाखों स्कूलों की स्थिति असंतोषजनक है और इस दिशा में गंभीर प्रयास की मांग की जाती है।

वोट चोरी के सबूतों का हाइडोजन बम

66

भाजपा ने हाइड्रोजन बम को सीधे अहिंसा से भी जोड़ा था, मानो गांधीजी के विचारों पर भाजपा से बेहतर कोई और नहीं चलता। भाजपा राहुल गांधी को हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश करती रही और सितम्बर के बाद अक्टूबर भी बीत गया तो पार्टी काफी हद तक निश्चित हो गई थी कि अब राहुल का हाइड्रोजन बम नहीं फूटने वाला। लेकिन भाजपा को शायद यह अनुमान नहीं था कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले फिर नए सबूतों के साथ देश को बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर लाखों वोटों की हेरा-फेरी की है। 5 नवंबर बुधवार की सुबह खबर आई कि 12 बजे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं, इसी के साथ तस्वीरें आईं जिनमें सामान ढोने वाली ट्रॉली में कागजात के ऊंचे-ऊंचे बंडल लाए जा रहे थे। तभी समझ आ गया था कि राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की चेतावनी सितम्बर में दी थी, अब उसका धमाका होने वाला है।

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद 1 सितम्बर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि वे अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तब भाजपा ने उनका आदतन या रणनीति के तहत मजाक उड़ाया था कि राहुल कांग्रेस को चुनाव नहीं जिता सकते तो वोट चोरी का बहाना बनाते हैं। भाजपा ने हाइड्रोजन बम को सीधे



अहिंसा से भी जोड़ा था, मानो गांधीजी के विचारों पर भाजपा से बेहतर कोई और नहीं चलता। भाजपा राहुल गांधी को हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश करती रही और सितम्बर के बाद अक्टूबर भी बीत गया तो पार्टी काफी हद तक निश्चित हो गई थी कि अब राहुल का हाइड्रोजन बम नहीं फूटने वाला। लेकिन भाजपा को शायद यह अनुमान नहीं था कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले फिर नए सबूतों के साथ देश को बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ

मिलकर लाखों वोटों की हेरा-फेरी की है। 5 नवंबर बुधवार की सुबह खबर आई कि 12 बजे राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं, इसी के साथ तस्वीरें आईं जिनमें सामान ढोने वाली ट्रॉली में कागजात के ऊंचे-ऊंचे बंडल लाए जा रहे थे। तभी समझ आ गया था कि राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की चेतावनी में लंबी-चौड़ी सफाई सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इससे पता चलता है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की तैयारी पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने कर ली थी। हालांकि राहुल गांधी ने बड़े आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे हैं। उनकी तरफ से इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया है ज्ञात हो कि हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारी जीत तय है और सारी व्यवस्था हो गई है। इस व्यवस्था शब्द को पकड़ कर राहुल गांधी ने बताया कि भाजपा की चुनावी रणनीति में इसका असली मतलब क्या है। किस तरह चुनाव आयोग को जरिया बनाकर भाजपा धांधली करवा रही है। लेकिन किरण रिजौजू का कहना है कि व्यवस्था का मतलब हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है, जो चुनाव जिताने में मेहनत करते हैं। हालांकि इस बार-पलटवार से उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। जैसे मतदाता सूची में राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा दिखाया, जिसका नाम 22 जगहों पर मतदाता के तौर पर दर्ज था। एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि मकान नंबर शून्य उन्हें दिया जाता है, जो दुर्भाग्यशाली लोग बेघर होते हैं। जो लैपपोस्ट के नीचे वा फुटपाथ पर रहते हैं। लेकिन हरियाणा की मतदाता सूची में मकान नंबर शून्य वाले कई मतदाताओं के पास बड़े घर का

मालिकाना हक राहुल गांधी ने दिखा दिया। राहुल गांधी ने बताया कि कुछ भाजपा नेता और उनके रिश्तेदार जो उत्तरप्रदेश में वोट डालते हैं, उनका नाम भी हरियाणा की वोटर लिस्ट में था। कई वोटर आईडी में फोटो एकदम धुंधली है और उस धुंधले चेहरे को कई बूथों पर वोटर के तौर पर राहुल गांधी ने दिखा दिया। ऐसी गलतियां दो-चार होती तब भी इन पर संदेह नहीं होता। हालांकि कम्प्यूटर और एआई की मदद से जब वोटर लिस्ट बनाई जा रही हो, तब ऐसी गलतियां शून्य होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में दस-बीस नहीं कम से कम 25 लाख मतदाताओं में इसका असली मतलब क्या है। राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस में कुछ लोगों की आपबीती भी सुनाई गई, जिनके नाम लोकसभा चुनावों के वक्त दर्ज थे और जिन्होंने वोट भी दिए थे। लेकिन विधानसभा में उनके नाम काट दिए गए। सविधान के तहत वयस्क मताधिकार का जो अनूठा उपहार भारतीय नागरिकों को मिला है, वह बेशकीमती है। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा के शासन में इस अनमोल तोहफे को चालाकी से छिना जा रहा है। इसलिए बुधवार को राहुल गांधी को सीधा आह्वान करना पड़ा कि जेन जी यानी नयी पीढ़ी के लोग अहिंसक तरीके से इस चोरी को रोकने और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएँ। खुद राहुल गांधी ने भी नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के पाले में भी राहुल ने गेंद डाल दी है कि वे खुद से इस वोट चोरी को रोकने

के लिए आगे आते हैं या नहीं। गौरतलब है कि इस समय एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। बिहार चुनाव शुरू होने से पहले ही इसे रोकने की याचिकाएं दर्ज करा दी गई थीं, इन पर कई बार अदालत बैठ चुकी है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उधर देश भर में अब एसआईआर की कवायद शुरू हो गई है। जबकि तमिलनाडु, प.बंगाल और महाराष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है। ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची शुद्धिकरण की बात करते हैं। लेकिन अब उन्हें बताना चाहिए कि 2 करोड़ मतदाताओं वाले हरियाणा में 25 लाख फर्जी मतदाताओं के सबूत राहुल गांधी दे चुके हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, ऐसे में उनका क्या जवाब है। क्या हर बार की तरह राहुल गांधी के इस दावे पर भी फेक का ठप्पा चुनाव आयोग लगा देगा। याद रहे कि अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के सबूत दिए थे। जिसमें एक ही मकान पर कई लोगों का पता दर्ज होने, फर्जी पते वा नाम या उम्र या लिंग के साथ मतदाता के तौर पर दर्ज होने, एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक जगहों के मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) होने के सबूत आए थे और फिर सितम्बर में अल्ट्रं सीट पर ऐसे ही सबूत पेश किए थे। लेकिन हर बार राहुल के दावों को खारिज किया गया। क्या इस रवैये के साथ लोकतंत्र बचा रहेगा, यह बड़ा सवाल है।

साहित्य सत्य की साधना और संस्कृति का पर्याय



संजीव ठाकुर
भारतीय अवाचीन संस्कृति का दार्शनिक चिंतन सदैव इस बात पर केन्द्रित रहा है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना का संवाहक है। यह चेतना जब अभिव्यक्ति के किसी व्यक्ति रूप में प्रवाहित होती है, तो वही अभिव्यक्ति का परिवर्जित रूप साहित्य कहलाती है। साहित्य कोई स्थिर संस्था नहीं, बल्कि वह एक जीवंत अनुभूति जो समय, समाज और संवेदना के साथ निरंतर विकसित होती रहती है। यह सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना भी। जब मनुष्य अपनी आत्मा के स्पंदन को शब्दों में डालता है,

शुद्ध, जीवंत और उत्कृष्ट साहित्य समाज की संवेदना का आधारस्तंभ होता है। यह मानव के भीतर छिपी उस सहज वृत्ति को जाग्रत करता है जो करुणा, प्रेम, समरसता और नैतिकता से पोषित होती है। साहित्य की यही शाश्वतता उसे कालजयी बनाती है। इसीलिए कालिदास, सूरदास, कबीर, प्रेमचंद या शेक्सपियर जैसे रचनाकार आज भी हमारे समय में उतने ही जीवंत प्रतीत होते हैं, जितने अपने समय में थे। उनकी कृतियाँ केवल शब्दों का सौंदर्य नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा का दर्तावेज हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य की पीड़ा, आशा, संघर्ष और संवेदना युगों के अंतराल में भी नहीं बदलती केवल उसका रूप बदलता है। राजनीतिक और भौगोलिक विभाजनों के बावजूद साहित्य मनुष्य को एक ही धरातल पर लाता है। क्योंकि शब्द का संसार सीमाओं से परे है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि ष्पापाएँ भिन्न हो सकती हैं, पर भाव एक ही रहते हैं। किसी भी देश की भाषा और साहित्य उस देश की सभ्यता, संस्कृति और मानसिक प्रगति का सूचक होते हैं। साहित्य के अध्ययन से उस समाज की आत्मा को समझा जा सकता है। उसके उल्लास, उसके संघर्ष, उसके स्वप्न और उसकी पीड़ाओं को भी। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा था। यह परिभाषा आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक लगती है। क्योंकि साहित्य केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं, बल्कि समाज के नैतिक संकटों का दर्पण भी है। यह विसंगतियों को उजागर करता है, अन्याय पर गंभीर प्रश्न उठाता है, और व्यक्ति के अंतस में छिपे विवेक को जगाता है।

स्वप्न और उसकी पीड़ाओं को भी। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा था। यह परिभाषा आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक लगती है। क्योंकि साहित्य केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं, बल्कि समाज के नैतिक संकटों का दर्पण भी है। यह विसंगतियों को उजागर करता है, अन्याय पर गंभीर प्रश्न उठाता है, और व्यक्ति के अंतस में छिपे विवेक को जगाता है। एक सशक्त लेखक अपने समय की संवेदना का प्रकट होता है। वह शब्दों के माध्यम से उस मीन को आवाज देता है जो अक्सर व्यवस्था, भव या मोह में दब जाता है। प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक लेखकों तक, हर युग का साहित्य मानवता

का संपूर्ण चरित्र चित्रण करता है। संस्कृति और साहित्य का संबंध उतना ही गहरा है जितना नदी और जल का। दोनों एक-दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। संस्कृति जहाँ मूल्य, परंपरा और आस्था का प्रतिरिचित्र करती है, वहीं साहित्य उन मूल्यों को शब्दों में ढालकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रवाहित करता है। यही कारण है कि जब समाज किसी मूल्य संकट से गुजरता है, तो सृजनशील साहित्य ही उसे उभे दिशा देता है। स्वतंत्रता युग में जब मौलिकता ने मनुष्य की संवेदना को लाम्हा ढँक दिया है, जब सूचना का विस्फोट तो है पर अनुभूति का अभाव है, तब साहित्य की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आज का साहित्य केवल विचार का नहीं, बल्कि विवेक का

वोट बैंक के कारण होते हैं धार्मिक आयोजनों में हादसे

66
मंदिर एक निजी तीर्थस्थल था, जो धर्मस्व विभाग के तहत पंजीकृत नहीं था। कार्यक्रम आयोजकों ने इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। देश में होने वाले धार्मिक आयोजनों में लापरवाही और कानून के उल्लंघन की सत्तारुढ़ दल और नेता अनदेखी करते रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह कि कहीं उनका वोट बैंक हाथ से नहीं खिसक नहीं जाए। इसलिए वे कानून उल्लंघन से होने वाले संभावित हादसों की अनदेखी करते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर किसी एक हादसे के बाद ऐसे हादसों की देश में पुनरावृत्ति होती रहे। वेकंटेस्वर मंदिर में हुआ हादसा इसका नया प्रमाण है। ये पहली बार नहीं है, जब किसी मंदिर में ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी हजारों लोगों की ऐसी घटनाओं में दर्दनाक मौत हो चुकी है। साल 2005 को महाराष्ट्र के मंथारदेवी मंदिर में 350 से अधिक भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में साल 2008 में नैना देवी मंदिर मची भगदड़ में 162 की जान गई थी। 30 सितम्बर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में वामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह से मची में 250 श्रद्धालु मारे गए। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोग मारे गए। भगदड़ की शुरुआत इस अफवाह से हुई कि जिस नदी के पुल को श्रद्धालु पार कर रहे थे, वह टूटने वाला है। 31 मार्च, 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन 'बावड़ी' या कुएं के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई।

आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 'पुष्करम' त्योहार के उद्घाटन के दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर-की-पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। आंध्र प्रदेश में काशीबुग्गा शहर के वेकंटेस्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। मंदिर एक निजी तीर्थस्थल था, जो धर्मस्व विभाग के तहत पंजीकृत नहीं था। कार्यक्रम आयोजकों ने इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। देश में होने वाले धार्मिक आयोजनों में लापरवाही और कानून के उल्लंघन की सत्तारुढ़ दल और नेता अनदेखी करते रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह कि कहीं उनका वोट बैंक हाथ से नहीं खिसक नहीं जाए। इसलिए वे कानून उल्लंघन से होने वाले संभावित हादसों की अनदेखी करते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर किसी एक हादसे के बाद ऐसे हादसों

की देश में पुनरावृत्ति होती रहे। वेकंटेस्वर मंदिर में हुआ हादसा इसका नया प्रमाण है। ये पहली बार नहीं है, जब किसी मंदिर में ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी हजारों लोगों की ऐसी घटनाओं में दर्दनाक मौत हो चुकी है। साल 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंथारदेवी मंदिर में 350 से अधिक भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में साल 2008 में नैना देवी मंदिर मची भगदड़ में 162 की जान गई थी। 30 सितम्बर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में वामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह से मची में 250 श्रद्धालु मारे गए। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोग मारे गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोग मारे गए। भगदड़ की शुरुआत इस अफवाह से हुई कि जिस नदी के पुल को श्रद्धालु पार कर रहे थे, वह टूटने वाला है। 31 मार्च, 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में हवन कार्यक्रम के दौरान एक

प्राचीन 'बावड़ी' या कुएं के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 14 जनवरी, 2011 को केरल के इडुक्की जिले के सबरीमाला में पुलमेदु में एक जीप से लौट रहे तीर्थ यात्रियों से टकरा गई, जिससे भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 13 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र समारोह में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ से 32 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल टूटने से लगभग 20 लोग मारे गए। 1 जनवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में 'पुष्करम' त्योहार के उद्घाटन के दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। 18 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर-की-पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी। लोग स्वयंभू बाबा से मुफ्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई 2025 को करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। 3 मई, 2025 को गोवा के शिरगांव गांव में श्री लाईराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान अचानक भगदड़ मचने से छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाकी रिपोर्ट्स में आंकड़े काफी ज्यादा बताए गए। इन हादसों में घायलों की संख्या भी हजारों में रही। इन सभी हादसों में एक बात समान है कि भीड़ जमा हुई थी और लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन ऐसी घटनाएं बार-बार लौट कर पुराने हादसों के जखम हरे कर देती हैं। बड़ा आयोजन, बड़ी भीड़ और बड़े हादसे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धार्मिक आयोजन में क्यों मचती है भगदड़ और कैसे मरते हैं लोग? अक्सर जब हादसे होते हैं, जांच रिपोर्ट सामने आती हैं तो प्रशासनिक

गलती सामने आती है। आस्था, नाकाफी इंतजाम, कम जगह में ज्यादा श्रद्धालु और मौसम को देखी ठहराया जाता है। कई हादसों की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। रिपोर्ट में कई बार तो कहा गया कि अफरातफरी के बीच लोगों की मौत दम घुटने को लेकर हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2019 के बीच देश दुनिया में भगदड़ की बड़ी घटनाएं हुए उनमें करीब 79 फीसदी मामले धार्मिक आयोजन के दौरान हुए थे। रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार भारत में धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के प्रमुख कारणों में भौगोलिक स्थान का विशेष महत्व है। भगदड़ की वजह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे डाल, दलदली इलाका, कीचड़ युक्त मैदान, खड़ी ढलान और बरखिरी से बचाव के इंतजाम न होने के चलते होता है। जबकि विदेशों में म्यूजिक कंसर्ट, स्टेडियम और नाइट क्लबों में होता है। आयोजन स्थल पर भीड़ कितनी आएगी, स्थान विशेष पर कितना लोगों का दबाव होगा, इसकी सटीक जानकारी और बेहतर इंतजाम हो तो हादसे को कंट्रोल किया जा सकता है। कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भीड़ काबू में ला जा सकता है। इन हादसों को रोकना जा सकता है, अगर क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। भीड़ को दबाव को लाइन में लगाकर कम कर लें। भगदड़ की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम रखें और वीवीआईपी मेहमानों के लिए सही तरीके से आगमन का इंतजाम रखें। बैरिकेड लगाकर, स्नेक लाइन एप्रोच बनाकर भीड़ को काबू में किया जा सकता है। ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भगदड़ के प्रभाव को न्यूट्रल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि घटनास्थल वाले जिले का प्रशासन इन उपायों से वाकिफ नहीं हो, किन्तु लापरवाही और धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप से नेताओं के वोट बैंक बिगड़ने का भय इसमें आड़े आता है। जब तक यह संकीर्ण सोच बनी रहेगी, तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक : किरायेदारी पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में राहत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रि परिषद की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी विभागीय कर्मचारी ही वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क करेंगे। इसी तरह किरायेदारी पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। इससे मकान मालिक एवं किरायेदारों के बीच होने वाले विवाद कम होंगे। लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे लेकर समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी ह्राएक परिवार-एक पहचानहू प्रणाली से पात्र

लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर सूची स्वतः तैयार होगी, जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एएसएमएन, व्हाट्सऐप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी, उनसे ग्राम पंचायत

सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृ त करें गे और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। इसी तरह वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि भवन स्वामी और किरायेदार दोनों किरायानामा लिखित रूप में तैयार करें और रजिस्ट्री कराएं, जिससे विवाद कम हों। एक वर्ष से अधिक अवधि की किरायेदारी विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है, लेकिन आमतौर पर अधिकांश

डिजिटल तकनीकी से आई पारदर्शिता : शाही

लखनऊ। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत 72वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का शुभारम्भ करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संघे शक्ति कल्युगे। संघ की शक्ति को देखना है तो, उसकी झलक सहकारिता वर्ष में दिखाई देती है। वर्ष 2017 के पहले सहकारिता विभाग की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। 2017 में योगी सरकार बनने के उपरान्त सहकारिता विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे है। प्रदेश के किसानों का विश्वास इसमें बड़ा है। करोड़ों लोगों के जनधन के खाते खोले गये। किसान सम्मान निधि को अनुदान राशि अब सीधे किसानों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। इसमें 50 लाख सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता

राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर विहिप की बैठक

लखनऊ। शहर के निराला नगर में स्थित भारतीय शिक्षा संस्थान में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत की विशेष बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप ने संगठन के इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। इसमें विहिप सदस्यों की स्वागत, आवास, सुरक्षा और परिवहन जैसी जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सशक्त, संगठित और जागरूक हिंदू समाज के निर्माण का प्रतीक है। साथ ही अन्य दो बिंदुओं धर्म रक्षा निधि और प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में कार्यकर्ता निर्माण पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप, प्रांत मंत्री देवेन्द्र प्रांत, सह मंत्री अविनाश, प्रवीण, अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख नृपेन्द्र विक्रम सिंह एवं विवेक मौजूद रहे।

पीओएस से एक करोड़ किसानों ने खरीदी खाद : कृषि मंत्री

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रबी सीजन में किसानों को बीज एवं उर्वरक की निर्बाध उपलब्धता की व्यापक तैयारी की गई है। रबी 2024-25 में 7.86 लाख कि्वंटल बीज अनुदान पर वितरित किया गया था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 11.12 लाख कि्वंटल का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तोरिया, सरसों एवं अलसी सहित सभी प्रमुख फसलों हेतु लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनके सापेक्ष 81 प्रतिशत बीज उपलब्धता तथा 69 प्रतिशत वितरण पूर्ण कर लिया गया है। लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दलहन की फसलों के 92,518 मिनीकिट (12,413 कु.) का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धता एवं 76,258 मिनीकिट (10,310 कु.) का वितरण सम्पन्न हो चुका है। साथ ही नेशनल मिशन ऑन एंडिबल ऑयल्स कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लस्टर प्रदर्शन तथा गन्ने के साथ अंतःफसली खेती हेतु 5,700 कु. सरसों का बीज किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति संतोषजनक है। 01 अक्टूबर से 13 नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में 17.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 10.00 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 7.56 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 4.09 लाख मीट्रिक टन एसएसपी एवं 1.51 लाख मीट्रिक टन एमओपी उपलब्ध रहा। इन्हीं तिथियों के बीच 4.82 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 6.24 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा 3.62 लाख मीट्रिक टन एनपीके का वितरण किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग एवं टैगिंग के मामलों में विभाग ने कठोर कार्रवाई की है।

एआरटीओ और पीटीओ समेत आठ के खिलाफ एफआईआर, दो गिरफ्तार

लखनऊ (संवाददाता)। एसटीएफ और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ओवरलोडिंग के नाम पर भ्रष्टाचार के रैकेट का पदार्फाश किया गया है। एआरटीओ और पीटीओ समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ को शिकायतें मिल रही थीं कि यूपी में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ओवरलोड वाहन रिश्वत देकर मौरंग और मिट्टी लेकर सीमा पार कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।एसटीएफ ने मामले में एआरटीओ लखनऊ उत्तर कमिश्नरेट राजू बंसल, पीटीओ मनोज भारद्वाज, दलाल अभिनव पांडेय, रितेश पांडेय, चालक कपिल, विनोद यादव, दीवान अनुज, दीवान गिरिजेश और सुनील सचान के खिलाफ मड़ियाव थाना में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

एसटीएफ ने अब तक बोधेपुर छजन सीतापुर निवासी दलाल अभिनव और कानपुर नगर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच मोबाइल, दो रजिस्टर, आधार कार्ड, एक कार और एक डंपर जब्त किया है।एसटीएफ को सूचना मिली कि दलाल अभिनव पांडेय ओवरलोड वाहनों को पास कराने का काम करता है और खदरी से सीतापुर की ओर जाने वाला है। एसटीएफ ने उसे भिठीली ओवरब्रिज के पास दबोच लिया। पुछताछ में अभिनव ने बताया कि भाई रितेश और सानू, आरटीओ व पीटीओ अधिकारियों की मिलीभगत से ओवरलोड ट्रकों को पास करवाते हैं तथा इसके एवज में प्रति वाहन तय रकम वसूली जाती है। वह प्रति वाहन 5,500 से 8,000 रुपये लेकर ट्रकों को बिना रोक-टोक आगे बढ़ने देता था।अभिनव

पांडेय की निशानदेही पर एसटीएफ टीम आईआईएम तिराहे पर पहुंची और सीतापुर की ओर से आने वाला ओवरलोड मौरंग से भरा एक डंपर पकड़ा गया। चालक कपिल ने बताया कि आरटीओ कार्यालय की रफ़ीसश् अभिनव पांडेय के माध्यम से पहले ही दे दी गई थी, इसलिए कोई अधिकारी उसे नहीं रोकेगा। पकड़े गए डंपर का वजन तौलने पर 66,340 किलो यानि 66.34 टन पाया गया, जबकि अनुमति इससे काफ़ी कम है।अभिनव पांडेय की कार से 2011 की एक पुरानी डायरी और नोटबुक मिली, जिसमें ओवरलोड वाहनों से वसूली गई धनराशि का विस्तृत विवरण दर्ज था। इसकी मोबाइल में 122 सदस्यों वाला एक व्हाट्सऐप ग्रुप मिला, जिसमें लोकेशन क्लियरेंस और निर्बाध परिवहन से संबंधित सदेश एवं ऑडियो मिले।

लखनऊ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गन्ना विभाग द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश-समर्थ उत्तर प्रदेश मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील भारत का था। उन्होंने कहा कि आज बिहार में जो नतीजे आए हैं वह चौकाने वाले हैं। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से एसआईआर के नाम पर बिहार के लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाने तथा उन्हें वोट के अधिकार से वंचित रखना देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना उत्तर प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों में भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऐसे में हमें बहुत ही सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है, एसआईआर के नाम पर हो रही वोट चारी की धांधली को रोककर भाजपा और चुनाव आयोग को बेनकाब करना है।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर और डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की।

पीजीआई के पास अतिक्रमण मामलानिपटएएलडीए : हाईकोर्ट

विधि संवाददाता लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एलडीए के विहित प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह पीजीआई के आसपास अतिक्रमण संबंधी मामले का दो माह में निस्तारण करें। इसी के साथ अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ को भी निर्देशित किया है कि उक्त के संबंध में जो अपील उनके समक्ष विचाराधीन है, उसका भी दो माह में निस्तारण किया जाए। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय निवासी प्रेम शंकर पांडेय की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में राजधानी के अस्पतालों के आस-पास से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का आग्रह किया गया था। साथ ही पीजीआई के मेन गेट के सामने और आस पास अतिक्रमण को हटाए जाने की गुजारिश की गई थी। जिससे वहां खास तौर पर एम्बुलेंस व अन्य जरूरी वाहनों व लोगों का आवागमन सुचारु हो सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि अब पीजीआई के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं है। वहां दूसरा गेट भी खोल दिया गया है। एलडीए के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि कुछ दुकानदारों के मामले विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हैं। कोर्ट ने इन मामलों का दो माह में निपटारा करने के निर्देश देकर याचिका निस्तारित कर दी।

ताजा खबर...

पत्रकार पर हमला करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ पुलिस ने मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक स्थानीय पत्रकार पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।स्थानीय पत्रकार और मोहनलालगंज निवासी मुकेश द्विवेदी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि बृहस्पतिवार (13 नवंबर) शाम करीब 5.40 बजे वह और हिमांशु रावत एक सर्विस सेंटर से अपनी कार (एसयूवी) लेकर जा रहे थे।तभी दो एसयूवी और एक अन्य कार ने उनके वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की। जब द्विवेदी अपने भूखंड पर पहुंचे और अपने लोगों को बुलाया, तो तीनों गाड़ियां (दो एसयूवी और एक कार) भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई।द्विवेदी ने आरोप लगाया कि जब उनका हमलावरों से आमना-समना हुआ तो उन्होंने उनको लक्ष्य करके गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गाड़ियों में सवार लोगों ने उनके साथ गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।

आज लखनऊ आएंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

लखनऊ (संवाददाता)। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार 15 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री शनिवार दोपहर 11.40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से सदर जाएंगे और वहां संस्कृत पाठशाला ऑडिटोरियम में और शाम को 4.00 बजे राजाजीपुरम में राजकुमार चिल्ड्रन एकेडमी में वरिष्ठ कार्यकर्ता जन संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सेठ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास जाएंगे। अगले दिन रविवार को अपराह्न 12.00 बजे सेक्टर-19 पासी चौराहा वृंदावन कॉलोनी में शहीद वीरांगना ऊदा देवी के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत अपराह्न 1.00 बजे वृंदावन कॉलोनी से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और अपराह्न 01.20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

प्रोविजन स्टोर में लगी भीषण आग

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र स्थित एक प्रोविजन स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। रात करीब 3 बजे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम पर दी गई। सूचना पर हजरतगंज फायर स्टेशन से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक, गुलामी कसाई मस्जिद के सामने रोड पर स्थित प्रोविजन स्टोर में आग लगी थी। स्टोर महेश साहू का है। जब दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान के भीतर सामान धधक रहा था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दुकान का लोहे का शटर भी गर्म होकर पूरी तरह लाल हो चुका था। आग तेजी से फैल रही थी और आसपास की दुकानों तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया था। स्थिति की गंभीरता देखते हुए फायरकर्मीयों ने आग को चारों दिशाओं से घेरकर काबू करने का प्रयास शुरू किया। टीम ने करीब एक घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलाया। दमकलकर्मीयों की मुस्तैदी के कारण आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। पास की अन्य दुकानों को नुकसान से बचा लिया गया। टीम कुछ देर और देर से पहुंचती तो आग फैलकर बड़ा हादसा बन सकती थी। हालांकि, दुकान में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आया है कि शाटं सफ़िट की वजह से आग लगी थी।

सीने में दर्द उठा,इयूटी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल की मौत

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनके सीने दर्द उठा। साथी पुलिसकर्मीयों ने उन्हें तौलते आस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक हेड कॉन्स्टेबल की पहचान रामपाल पांडेय (58) के रूप में हुई।रामपाल मूलरूप से अमेठी के नरहपुर के रहने वाले थे। वह महानगर पुलिस लाइन में तैनात थे। पास में ही किगए के मकान में रहते थे। मौजूदा समय में उनकी इयूटी निरालानगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी थी। इसके पहले वह मंत्री दया शंकर सिंह की सुरक्षा में तैनात थे। परिजनों के मुताबिक, सुबह रामपाल के साथी ने बेटे अमित को फोन किया। बताया कि इयूटी के दौरान अचानक रामपाल के सीनेमें तेज दर्द हुआ है। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।लखनऊ पहुंचने पर परिवार को पत चला कि उन्हें मृत घोषित किया जा चुका। अचानक हुई इस घटना से परिवार सदमे में है। घर में पत्नी ज्ञान पांडेय और तीन बेटे नीरज, अमित और शैलेंद्र हैं। पुलिस विभाग ने हेड कॉन्स्टेबल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री कंपोजिट विद्यालय सेमरामऊ में बच्चों ने मनाया बड़े ही हर्षोल्लास से बाल दिवस कार्यक्रम



सजाई जिसे बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता ने भी की जमकर खरीदारी विद्यालय परिसर में बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला बच्चों ने बहुत मन लुभावन दुकानें लगाई कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ शिखा सिंह विनीत कौशल रेनू यादव रामबाबू वर्मा प्रीति सिंह तथा शिखा चौरसिया सुनील कुमार आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा

ददरी मेला में दंगल प्रतियोगिता सम्पन्न, अर्जुन यादव बने जिला केसरी

बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला के अवसर पर आयोजित दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल दौर में धनंजय यादव (बेल्थारोड), कृष्ण यादव (सिकंदरपुर), अर्जुन यादव (बच्छईपुर) एवं सर्वेश यादव (रसड़ा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जगह बनाई। रोमांचक फाइनल मुकाबले में



बच्छईपुर निवासी अर्जुन यादव ने रसड़ा के सर्वेश यादव को पराजित कर 'जिला केसरी' का खिताब अपने नाम किया। अर्जुन यादव ने 10 पॉइंट हासिल किए, जबकि सर्वेश यादव 2 पॉइंट लेकर उपविजेता रहे। दंगल में बड़ी संख्या में दर्शकों ने उत्साहपूर्वक पहलवानों का हौसला बढ़ाया। विजेता पहलवान को मेले समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस आयोजन से पारंपरिक खेल कुश्ती को नई ऊर्जा मिली और युवाओं में उत्साह का संचार हुआ।

भरौली पुल से ट्रकों के अवैध परिवहन पर सख्ती, जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

अवैध ट्रक संचालन पर जिला प्रशासन सख्त, भरौली व माझीघाट पर लगेगेंगे हाई-क्वालिटी कैमरे

नंबर प्लेट ढककर ट्रक पार कराने वालों पर होगी कार्रवाई, भरौली पुल पर 24 घंटे निगरानी टीम तैनात रहेगी बलिया। बिहार की ओर से आने-जाने वाले ट्रकों के अवैध परिवहन और राजस्व हानि की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भरौली मार्ग से प्रतिदिन लगभग 700 ट्रक गुजरते हैं। कई ट्रक चालक आईएसटीपी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) से बचने के लिए नंबर प्लेट ढकने या बदलने जैसी अवैध हरकतें करते हैं, जिससे



प्रतिदिन कई लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि भरौली पुल पर उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाकर उन्हें आईएसआईपी सिस्टम से जोड़ा जाए। साथ ही माझीघाट पर भी कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश खनन अधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी के लिए परिवहन विभाग, खनन विभाग, पुलिस एवं एक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम बनाई जाए। एक टीम भरौली पुल और दूसरी टीम माझीघाट पर तैनात रहेगी।

जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जिले के लगभग 50 ट्रक मालिकों पर कई बार चालान काटा गया है, लेकिन उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया है। इससे राजस्व की क्षति हो रही है। इस पर उन्होंने परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे ट्रक मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए वसूली की जाए, एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त किए जाएं ताकि अन्य लोग भी सबक लें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एडीएम अनिल कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ददरी मेला में बलिया के कलाकारों को मिलेगा मंच, रजिस्ट्रेशन शुरू

बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला 2025 में इस बार स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की नई पहल की जा रही है। बलिया के उभरते कलाकारों को अपनी कला और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की विशेष व्यवस्था की गई है।

मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बताया कि बलिया के कलाकार गायन, नृत्य, वादन, नाटक, कवि और हास्य जैसी विधाओं में अपनी प्रस्तुति देने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। यह पहल स्थानीय कलाकारों को पहचान और सम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कलाकारों को अपना रजिस्ट्रेशन अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) के पास मोबाइल नंबर 9792281554 पर या ददरी मेला सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित होकर कराना होगा। पंजीकृत कलाकारों को मेला अवधि में मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

ददरी मेला 2025 में पहली बार होगा ‘ददरी मेला क्रिकेट कुंभ’

बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला में इस वर्ष खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक पहल की जा रही है। पहली बार मेले में ‘ददरी मेला क्रिकेट कुंभ’ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा, जबकि 29 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बताया कि इस क्रिकेट कुंभ में लगभग 100 टीमें भाग लेंगी। टीमें अपना पंजीकरण जिला क्रीड़ा अधिकारी (मोबाइल नंबर 9415842138) पर करा सकती हैं। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैच 5 ओवर के प्रारूप में खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे और हर गेंदबाज को केवल एक ओवर फेंकने की अनुमति होगी। सभी मैच केनवास बॉल से खेले जाएंगे ताकि खेल में रोमांच बना रहे। मेले के दौरान खेल के साथ-साथ सांस्कृतिक विभाग की टीम भी मंच पर गायन और वादन प्रस्तुत करेगी, जिससे खेल के साथ मनोरंजन का भी आनंद लोगों को मिलेगा।

ददरी मेला में पहली बार उत्कृष्ट दुकानदार होंगे सम्मानित

बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला में इस वर्ष एक नई पहल की जा रही है। पहली बार मेले में दुकान व्यवसायियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान मेला समापन के दिन ददरी मंच से प्रदान किया जाएगा।

मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बताया कि दुकानदारों का चयन विभिन्न श्रेणियों में किया जाएगा, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। चयन की श्रेणियां इस प्रकार हैं, जिसमें वेंडर जोन, खानपान, मनोरंजन, सौंदर्य प्रसाधन, गृहस्थ वस्तुएं एवं बर्तन, वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र, लकड़ी का सामान, गृह साज-सज्जा, बाल वस्तुएं जैसे खिलौने व पुस्तकें, देशी वस्तुएं जैसे चोखा-बाटी, खाजा आदि।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा तैनात सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट इन दुकानों का चयन करेंगे। चयन के मुख्य आधार होंगे। जिसमें उत्पादों की शुद्धता एवं मानकता, दुकान की आकर्षक सजावट, ग्राहक व्यवहार स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन कैंटीरिंग सेवा की गुणवत्ता। उन्होंने कहा कि इस बार वेंडिंग जोन में टेला और पटरी पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े दुकानदारों तक सभी को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापारियों में उत्साह बढ़ाना और मेले की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है।

किसान पर तेंदुए का हमला, हालत गंभीर

मिर्हीपुरवा। खेत में गन्ना छील रहे एक किसान पर शुक्रवार दोपहर में तेंदुए ने हमला कर दिया, हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के दौड़ने पर उसकी जान बच सकी। जख्मी किसान को तुरंत पहुंचाकर भर्ती कराया गया। मुर्तिहा रेंज की वन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत है।

ग्राम खल्ला पुरैना, अमृतपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र (48) शुक्रवार को दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास परिजनों और अन्य ग्रामीणों के साथ अपने खेत



में गन्ना छील रहे थे। इसी दौरान घनी के घने खेत से निकले तेंदुए ने उन पर अचानक हमला कर दिया।

किसान के चिल्लाने पर थोड़ी दूरी पर काम कर रहे मजदूर हांका लगाते हुए दौड़े। शीड़ और शोर से तेंदुआ हरिश्चंद्र को छोड़कर गन्ने के खेत में जा घुसा और ओझल हो गया।

हमले में किसान के सिर और गले पर गहरे जख्म हुए हैं। गांव पहुंचे मुर्तिहा रेंज के वनक्षेत्र अधिकारी रत्नेश कुमार ने जख्मी हरिश्चंद्र को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्हीपुरवा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जख्मी किसान को

मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वनक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर तेंदुए के पगचिह्न मिले हैं। खेतों में कॉम्बिंग की जा रही है। रेंजर ने बाघ और तेंदुओं की सक्रियता को देखते हुए वन कर्मियों ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देउवनपुरवा से दो किलोमीटर है दूरी: देउवनपुरवा गांव में बृहस्पतिवार को तेंदुए ने हमला कर किसान भीखन को मारझाला था। 24 घंटे के अंदर महज दो किलोमीटर की दूरी पर तेंदुए का यह दूसरा हमला है।

लगाए गए पिंजरे, फॉग लाइट और कैमरे: वनक्षेत्र अधिकारी रत्नेश कुमार ने बताया कि दोपहर में हुए हमले को देखते हुए घटनास्थल के निकट एक पिंजरा, 6 थर्मोसैसर कैमरे और एक फॉग लाइट लगाई गई है। वहीं देउवनपुरवा गांव में बृहस्पतिवार को हुए हमले के बाद एक पिंजरा, 4 थर्मोसैसर कैमरे और एक फॉग लाइट लगाई गई। पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक सहायता: मिर्हीपुरवा सीएचसी पहुंचे वनक्षेत्र अधिकारी रत्नेश कुमार ने बताया कि दोपहर में हमले में घायल हरिश्चंद्र के इलाज के लिए पांच हजार की आर्थिक सहायता परिजनों को दी गई है। वहीं मृतक भीखन के परिवार को ककरहा रेंजर डीपी कनौजिया ने 5 हजार की अहेतुक सहायता राशि प्रदान की।

ददरी मेला 2025: संत समागम के आशीर्वाद से हुआ भव्य शुभारम्भ

संत समागम ने बढ़ाई ददरी मेले की गरिमा, सभी पंथों के संत हुए एकत्र महर्षि भृगु परंपरा में ददरी मेला आरंभ, 20 से अधिक संतों ने दिया आशीर्वचन संतों के आशीर्वचनों से गूंजा ददरी मेला भारतेंदु मंच पर दिखी अद्भुत छटा

बलिया। महर्षि भृगु की पौराणिक परंपरा में आयोजित ददरी मेला 2025 का शुभारम्भ शुक्रवार को भव्य संत समागम के साथ हुआ। इस परम पावन अवसर पर देशभर के विभिन्न पंथों और परंपराओं से आए 20 से अधिक पूज्य संतो ने अपने आशीर्वचन और प्रवचनों से ददरी मेला एवं भारतेंदु मंच को दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे सभी पूज्य संतो ने संयुक्त रूप से संपन्न कर संत समागम



गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। जिसमें श्री रामाशंकर दास जी महाराज, कामेश्वरधाम कारों, महामण्डलेश्वर कौशलेंद्र गिरि जी, श्रीनाथ मठ रसड़ा, ब्रह्माकुमारी उमा बहन, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी, श्री गुरुप्रीत सिंह जी, रागी हजूरी, सिख पंथ, पूज्य सुनीता तिवारी, गायत्री परिवार, आचार्य ज्ञानप्रकाश वैदिक जी, आर्य समाज, आनन्द गौरांग दास जी, इस्कॉन, श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय जी, उपादेष्टा, विहंगम योग, भंते राहुल जी, बौद्ध धम्म, श्रीमहंत उमाशंकर साहब, कबीर पंथ, श्रीमहंत गंगासागर शास्त्री जी, दरिया साहब पंथ, श्री धनंजय शर्मा जी, जय गुरुदेव पंथ, सुदेश संत, गोंडवाना, श्री राम बदन दास, शाक्त पंथ, श्री सत्यप्रकाश, सतनामी पंथ, श्री श्रद्धानंद, विहंगम योग, श्री बालक बाबा, लखनेश्वर डीह, श्री योगी स्वामी, श्रीनाथ मठ रसड़ा, श्री भूमक राजेश गोंड, गोंडवाना, श्री सरदार रंजीत सिंह, सिख धर्म, श्रीअमरजीत सिंह, सिख धर्म, श्री सरदार अश्वण सिंह, सिख धर्म पूज्य संतों द्वारा ददरी मेला क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया। इस संत समागम के समन्वयक श्री कोशिकीय जी रहे। इस कार्यक्रम में सीआरओ त्रिभुवन आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने पीएम जन विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

बलिया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में आधार भूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। तहसील बेल्थारोड



के विकास खंड सीयर, ग्राम पंचायत गोविंदपुर दुगौली में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत वाले इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अलावा तहसील सिकंदरपुर के नगर पंचायत सिकंदरपुर में पाइप पेयजल व्यवस्था स्थापित करने संबंधी 40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने वाली यह परियोजना क्षेत्र की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करेगी। सभी प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने दोनों प्रोजेक्ट का प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर डीएम मंगला प्रसाद सिंह की बैठक, बीएलओ को मिली सख्त हिदायतें

बलिया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं गणना प्रपत्र वितरण की समीक्षा की गई।

डीएम ने बताया कि बूथ नंबर 27, बलिया नगर में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा कर लिया गया है। वहीं, बूथ नंबर 28 के बीएलओ ने भी 100 प्रतिशत वितरण होने की जानकारी दी। हालांकि राजनीतिक दलों की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ को गणना प्रपत्र की प्राप्ति का प्रमाण—पत्र सुरक्षित रखना होगा। बूथ नंबर 243, बलिया नगर में भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिकंदरपुर के बूथ नंबर 9 और बलिया नगर के बूथ नंबर 303 पर बीएलओ फील्ड में



नहीं दिखे हैं, इस पर भी कार्यवाही होगी। उन्होंने बूथ में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव 16 नवंबर तक देने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल भी अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की सूची निर्धारित प्रारूप में दें। और जिन दलों ने अभी तक बीएलए की नियुक्ति नहीं की है जल्द से जल्द नियुक्त कर उनकी सूची हमें उपलब्ध कराएं उन्होंने कहा, “बीएलओ और बीएलए मिलकर कार्य करेंगे तो मतदाता सूची का कार्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा।” डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिन राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए की तैनाती कर दी है, उनके साथ बीएलओ बैठक करें ताकि समन्वय बना रहे। बैठक में एडीएम अनिल कुमार एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।